भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2862

उत्तर देने की तारीख-07/08/2023

स्कूल जाने वाले बच्चों में पठन क्षमता की कमी

†2862 सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिक शिक्षा और बुनियादी अधिगम के लिए बजटीय व्यय का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को वार्षिक शिक्षा स्तर रिपोर्ट के द्वारा प्रकाशित अधिगम परिणाम रिपोर्ट की जानकारी है जिसमें यह बताया गया था कि वर्ष 2018 के 73 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2022 में आठवीं कक्षा के केवल 69.9 प्रतिशत छात्र ही कम से कम मूल पाठ पढ़ सकते हैं;

(ग) क्या सरकार की स्कूल जाने वाले बच्चों में अधिगम परिणामों को सुनिश्चित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) क्या सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों के अधिगम संबंधी परिणामों का निर्धारण करने के लिए अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क): स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं को मिलाकर स्कूल शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना समग्र शिक्षा शुरू की थी। फाउंडेशनल लर्निंग समग्र शिक्षा का एक अनिवार्य घटक है। इस योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति:2020 (एनईपी:2020) की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसे 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखा गया है।

समग्र शिक्षा के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय

वर्ष के दौरान आवंटित केंद्रीय हिस्सा नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटित किया गया केन्द्रीय हिस्सा
2020-21	28681.79
2021-22	28388.03
2022-23	35297.16
2023-24	35321.12

(ख): वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में जारी उपलब्धि सर्वेक्षण एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है।

(ग): समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक विस्तारित स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के सेवाकालीन प्रशिक्षण, उपलब्धि सर्वेक्षणों का संचालन, अनुकूल शिक्षण वातावरण प्रदान करने के लिए प्रत्येक स्कूल को समग्र स्कूल अनुदान, पुस्तकालय, खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुदान आदि जैसे विभिन्न पहलों के लिए सहायता प्रदान करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर फोकस करती है। योजना के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक नए स्कूल खोलने/उनका सुदृढीकरण, स्कूल भवनों और अतिरिक्त शिक्षण-कक्षों का निर्माण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उन्नयन और संचालन, आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों की स्थापना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और स्कूलों में अन्य सुविधाओं के प्रावधान शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी स्कूल निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, इसके अलावा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अन्य पहलें जैसे कि सेवारत शिक्षकों, मुख्याध्यापकों और प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण, शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए सुधारात्मक शिक्षण, स्कूलों को पुस्तकालय अनुदान का प्रावधान, आईसीटी और डिजिटल पहल, अध्यापक शिक्षा संस्थानों का सुदृढीकरण, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, पढ़े भारत बढ़े भारत, आदि शामिल है।

समग्र शिक्षा के तहत **समझ के साथ पढ़ने और संख्या ज्ञान में प्रवीणता हेतु राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत)** शुरू की गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में प्रत्येक बच्चा अनिवार्य रूप से ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) प्राप्त कर ले, तथा इसके लिए ई-सामग्री **दीक्षा** प्लेटफॉर्म पर जारी की गई है।

निष्ठा - शिक्षकों, मुख्य शिक्षकों/प्रधानाचार्यों और शैक्षणिक प्रबंधन में अन्य हितधारकों के लिए स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों के लिए शुरू किया गया एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

विद्या प्रवेश- 29 जुलाई, 2021 को कक्षा-I के बच्चों के लिए तीन माह के प्ले-आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चे जब अपनी ग्रेड-I की कक्षा में आएं तो उन्हें एक उत्साहपूर्ण और प्यार भरा वातावरण मिले।

(घ): भारत सरकार तीन वर्ष की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X के लिए नमूना आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) कार्यक्रम लागू कर रही है। एनएएस का अंतिम दौर 12 नवंबर, 2021 को पूरे भारत में आयोजित किया गया था जिसमें ग्रेड 3, 5, 8 और 10 के छात्र शामिल थे। एनएएस का लक्ष्य और उद्देश्य शिक्षा प्रणाली के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिगम दक्षताओं का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। एनएएस 2021 के लिए राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला रिपोर्ट 25.05.2022 को जारी की गई हैं और यह ***http://nas.gov.in*** ***पर*** उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी (एफएलएस), भारतीय भाषाओं में समझ के साथ मौखिक पढ़ने के प्रवाह के लिए अपनी तरह का पहला बड़े पैमाने पर मूल्यांकन और बेंचमार्किंग अध्ययन मार्च 2022 में 20 भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, गारो, खासी, कोंकणी, गुजराती और नेपाली में आयोजित किया गया था, जिनका उपयोग विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जा रहा है। एफएलएस के लिए रिपोर्ट ***https://dsel.education.gov.in/fls_2022*** ***पर*** उपलब्ध है।

*****